भारत-ईयू व्यापार समझौता

# भारत के लिए 6.41 लाख करोड़ के निर्यात का खुला आसमान, यूरोप में बढ़ेगी भारतीय उत्पादों की पहुंच

## कपड़ा : 26.3 अरब डॉलर के निर्यात का खुलेगा रास्ता

टैरिफ : 12 फीसदी से घटकर शून्य



**7.2 अरब डॉलर** का कपड़ा निर्यात करता है भारत वर्तमान में ईयू को

भारत-ईयू एफटीए के लागू होने के बाद यूरोपीय संघ भारत से आयातित हर प्रकार के वस्त्रों (टेक्सटाइल, अपैरल और कपड़े) पर टैरिफ को 12 फीसदी से घटाकर शून्य कर देगा। यह उच्च अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित श्रम आधारित भारतीय कपड़ा निर्यात और एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़ी जीत है। शून्य टैरिफ से यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े काफी सस्ते हो जाएंगे। इससे बड़े खरीदारों के साथ अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के अवसर मिलेंगे। साथ ही, भारत के लिए ईयू के बाजारों में 26.35 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का रास्ता खुलेगा, जो अभी सिर्फ 7.2 अरब डॉलर है।

■ कीमतों के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने और आसान पहुंच से यूरोपीय संघ के बाजारों से भारत को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और सिलाई समेत उत्पादन बढ़ने से फैक्टरियों का लगातार इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार मिलेगा।

## चमड़ा व फुटवियर : कम मार्जिन वाले क्षेत्र की बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

टैरिफ : 17 फीसदी से घटकर शून्य



**100 अरब डॉलर** का है यूरोपीय संघ का फुटवियर और चमड़ा आयात बाजार

शून्य टैरिफ से भारतीय फुटवियर और चमड़ा निर्यात उद्योग की यूरोपीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां मार्जिन कम होता है और कीमतें खरीदारों के खरीद फैसलों पर असर डालती हैं। इससे न सिर्फ भारतीय कंपनियों को मास और मिड-प्रीमियम दोनों सेगमेंट में ईयू से नए ऑर्डर हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाली छोटी कंपनियों (एमएसएमई) को भी समर्थन मिलेगा और स्थायी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।

■ भारत 100 अरब डॉलर के ईयू के चमड़ा और फुटवियर आयात बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तैयार है। बेहतर प्रतिस्पर्धा से टैनिंग, फिनिशिंग, कंपोनेंट्स और फाइनल फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग में निर्यात बढ़ेगा।

## हस्तशिल्प-फर्नीचर : खुलेंगे नए अवसर, कारीगरों की बढ़ेगी कमाई

हस्तशिल्प, फर्नीचर और खेल के सामान को बेहतर पहुंच मिलना कारीगरों एवं एमएसएमई के लिए खासतौर पर फायदेमंद हो सकता है, जो छोटे कंसाइनमेंट में निर्यात करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार पैदा करते हैं। बारपेटा, बांस से बने फर्नीचर और शिल्प को नए अवसर मिलेंगे।



समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार मंत्री मारोस सेफ्कोविक। एजेंसी

## इलेक्ट्रॉनिक्स : विनिर्माण बढ़ाने में तेजी से मिलेगी मदद



टैरिफ : 14 फीसदी से घटकर शून्य

ज्यादातर उत्पादों पर करीब शून्य टैरिफ भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। इससे तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के साथ कंपोनेंट्स, सब-असेंबली और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मजबूती मिलेगी। यूरोपीय बाजारों में आसान पहुंच से बिल्ड इन इंडिया आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलेगी और भारत तेजी से निर्यात बढ़ाने में सक्षम होगा।

■ *एमएसएमई, आपूर्तिकर्ताओं, टेस्टिंग एवं रिपेयर सर्विसेज, टूलिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बड़े मैन्युफैक्चरर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा।*

## रत्न-आभूषण : बड़े यूरोपीय ब्रांड से मिलेंगे ऑर्डर, बढ़ेगा रोजगार



टैरिफ : चार फीसदी से घटकर शून्य

आभूषण कारोबार एवं निर्यात में कीमत के साथ रफ्तार, कारीगरी और विश्वसनीयता मायने रखती है। शून्य टैरिफ से डिजाइन और शुद्धता आधारित आभूषण निर्यात में यूरोपीय बाजारों के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़त मजबूत होगी। टैरिफ में कटौती से यूरोपीय बाजारों में पहुंच लागत कम होगी, जिससे प्लेन सोने और जड़े हुए आभूषणों की ईयू में मांग बढ़ेगी। यूरोपीय थोक विक्रेताओं एवं बड़े ब्रांड के साथ गहरे संबंध बनाने और नए ऑर्डर पाने के मौके भी मिलेंगे।

■ *यह क्षेत्र एमएसएमई-प्रधान और कारीगरों पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए, कटिंग, पॉलिशिंग, सेटिंग और फिनिशिंग के मोर्चे पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।*

## बड़े निर्यातकों के साथ एमएसएमई को विस्तार में मदद

**इंजीनियरिंग उत्पाद**

टैरिफ घटने और कई तरह के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच से यूरोपीय बाजारों में इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कई राज्यों के मैन्युफैक्चरिंग बेस एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। नए ऑर्डर मिलने और उत्पादन बढ़ने से बड़े निर्यातकों के साथ एमएसएमई सहायक कंपनियों को भी विस्तार करने में मदद मिलेगी।

## कृषि-समुद्री उत्पाद : बाजार पहुंच के लाभ से बढ़ेगी किसानों की आय

भारत ईयू के बाजारों में कृषि और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में सक्षम होगा। किसानों और तटीय इलाकों में रहने वालों की आय बढ़ेगी। मछली पालन, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी। काली मिर्च और इलायची जैसे मसाले यूरोप में बेहतर पहुंच का लाभ उठा सकते हैं।

## केमिकल्स : 97.5 फीसदी निर्यात टैरिफ : 12.8 फीसदी से घटकर शून्य

भारत के सर्वाधिक निर्यात के लिए तैयार मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में से एक को समर्थन मिलेगा। बल्क और स्पेशल केमिकल्स निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इसका लाभ गुजरात के भरूच-वडोदरा और महाराष्ट्र की केमिकल बेल्ट में होने की उम्मीद है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सहायक क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी।

## फार्मा-मेडिकल उपकरण : 11 फीसदी से घटकर शून्य टैरिफ



इस राहत से ईयू के बड़े फार्मा मार्केट में भारत की विस्तार क्षमता मजबूत होगी। मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढ़ाने के लिए संभावनाएं बेहतर होंगी, जहां कीमतों के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा मायने रखती है। साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं, पैकेजिंग, टेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के क्लस्टर का सपोर्ट मिलेगा।

## राज्यों के लिए भी निर्यात के बड़े मौके

### रोजगार के साथ बढ़ेगी कमाई



**पंजाब**
- लुधियाना गारमेंट्स और निटवियर
- जालंधर में बने खेल के सामान
- मंडी गोबिंदगढ़ की लाइट इंजीनियरिंग यूनिट्स को लाभ
- औद्योगिक नौकरियों और सहायक आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलेगी।

**उत्तर प्रदेश**
- कानपुर और आगरा में चमड़े से बने फुटवियर
- सहारनपुर से फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स
- नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग
- पश्चिमी यूपी से कृषि उत्पाद
- **अन्य लाभ** : इन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ने से बड़ी संख्या में सृजित होंगे रोजगार।

**असम**
- डिब्रूगढ़-जोरहाट से चाय
- ऊपरी असम से मसाले
- बारपेटा और नलबाड़ी बांस से फर्नीचर एवं हैंडीक्राफ्ट
- फार्मास्यूटिकल उत्पाद
- अन्य लाभ : बेहतर कीमत मिलने से उत्पादकों की बढ़ेगी आय।

**राजस्थान**
- जयपुर में बने गहने
- जोधपुर से लकड़ी के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट
- तुरु के स्पोर्ट्स गुड्स, बंधेज जैसे टेक्सटाइल और चमड़ा उत्पाद
- अन्य लाभ : एमएसएमई और कारीगर समुदाय की बढ़ेगी आय।

**गुजरात**
- सूरत से टेक्सटाइल, हीरे व आभूषण
- भरूच-वडोदरा से केमिकल निर्यात
- राजकोट से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद
- वेरावल से समुद्री उत्पादों का निर्यात
- अन्य लाभ : तटीय आजीविका, एमएसएमई और प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिलेगा समर्थन।

**पश्चिम बंगाल**
- उत्तरी बंगाल से दार्जिलिंग चाय
- दीघा एवं हल्दिया से झींगा और फ्रोजन मछली
- पारंपरिक हस्तशिल्प
- **अन्य लाभ** : छोटे उत्पादकों और स्थानीय वैल्यू एडिशन को मिलेगी मदद।

**तेलंगाना**
- हैदराबाद-वारंगल से टेक्सटाइल
- हैदराबाद से फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और इंजीनियरिंग उत्पाद
- अन्य लाभ : हाई-वैल्यू वैश्विक आपूर्ति शृंखला में मजबूत होगी राज्य की भूमिका।

**महाराष्ट्र**
- इचलकरंजी में तैयार कपड़े
- पुणे से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्र
- ठाणे-रायगढ़ से फार्मास्यूटिकल्स
- मुंबई से रत्न-आभूषण
- अन्य लाभ : श्रम-केंद्रित उत्पादन के साथ हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेंगे रोजगार।

**आंध्र प्रदेश**
- विशाखापत्तनम और काकीनाडा से झींगा एवं समुद्री खाद्य उत्पाद
- विशाखापत्तनम से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात
- **अन्य लाभ** : मछली पालन, प्रोसेसिंग और कोल्ड-चेन में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा मजबूत।

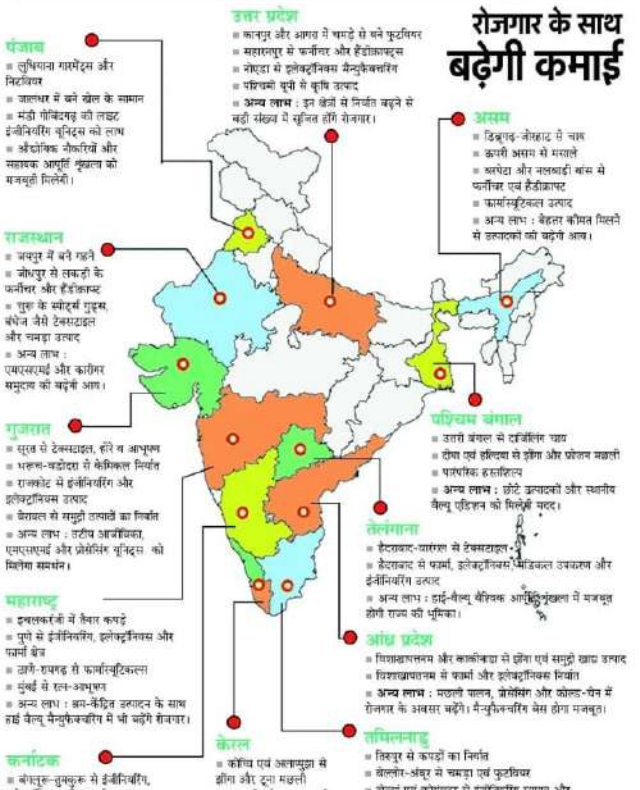

**कर्नाटक**
- बेंगलुरु-तुमकुरु से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा उत्पाद
- बेंगलुरु में तैयार कपड़े
- अन्य लाभ : हाई स्किल सेक्टर के साथ श्रम-केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग में मिलेंगे रोजगार।

**केरल**
- कोच्चि एवं अलाप्पुझा से झींगा और टूना मछली
- इडुक्की और वायनाड से काली मिर्च एवं इलायची
- अन्य लाभ : किसानों और मछुआरों की बढ़ेगी कमाई।

**तमिलनाडु**
- तिरुपुर से कपड़ों का निर्यात
- वेल्लोर-अंबूर से चमड़ा एवं फुटवियर
- चेन्नई एवं कोयंबटूर से इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग
- **अन्य लाभ** : मूल्य शृंखला को मिलेगी मजबूती। एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर्स को फायदा।

## आयात शुल्क में बड़ी कटौती से सस्ती होंगी लग्जरी कारें 2.90 करोड़ में मिलेगी 4.18 करोड़ की लैम्बॉर्गिनी उरुस

यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के तहत भारत बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और लैम्बॉर्गिनी जैसी लग्जरी कारों पर लगने वाले आयात शुल्क में धीरे-धीरे कटौती कर 110 फीसदी से 10 फीसदी कर देगा। इससे यूरोपीय देशों से आयातित लग्जरी कारों की कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच एफटीए लागू होने के बाद आयातित लग्जरी कार लैम्बॉर्गिनी उरुस की कीमत घटकर 2.90 करोड़ रुपये रह जाएगी, जिसकी वर्तमान में एक्स शोरूम कीमत 4.18 करोड़ रुपये है। कीमत में कटौती का यह अनुमान टैरिफ में कमी के आधार पर लगाया गया है। हालांकि, दाम में कटौती का अंतिम फैसला कंपनियों पर निर्भर करेगा।

**ऐसे घटेगा आयात शुल्क**

*शुरुआत में ड्यूटी को 40 फीसदी तक कम करने से कुल प्रभावी टैक्स का बोझ घटकर 70-90 फीसदी रह जाएगा। इससे वर्तमान की तुलना में कीमतें 40-50 फीसदी तक घट सकती हैं।*

अब तक, यूरोप से आयातित पूरी तरह से बनी (सीबीयू) कारों पर दुनिया के सबसे ऊंचे ऑटोमोटिव टैरिफ सिस्टम में से एक लागू है। वर्तमान में इन गाड़ियों पर 70 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी, 40 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, 28 फीसदी आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस लगता है। असल में, इससे कुल टैक्स एक कार की सीआईएफ (कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट) वैल्यू का लगभग 140-170 फीसदी हो जाता है।

■ एफटीए के तहत, पहले फेज में योग्य ईयू-निर्मित कारों के लिए शुल्क में तेजी से घटेगी, जो 40 फीसदी तक हो जाएगी। जीएसटी और सेस लगेगा। लंबे समय में, कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे कम होगा और आखिरकार 10 फीसदी पर आ जाएगा।